ISSN: 2393-8048
International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Multilingual, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =8.152, January-June 2025, Submitted in January 2025

आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की भूमिका : नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन

पूनम,शोधार्थी,(अर्थशास्त्र विभाग) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
डॉ0 रणधीर सिंह, सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र विभाग) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

शोध सारांश

प्रस्तुत शोध का केंद्रीय उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की भूमिका का विश्लेषण करते हुए भारत में लागू नई आर्थिक नीति के स्वरूप, उद्देश्यों, प्रभावों तथा उपलब्धियों का समग्र मूल्यांकन करना है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निवेश को उत्पादन, रोजगार, तकनीकी प्रगति, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख साधन माना जाता है। भारत में वर्ष 1991 के पश्चात अपनाई गई नई आर्थिक नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के पारंपरिक स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किए। इस नीति के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, विदेशी पूंजी एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अवसरों का विस्तार हुआ तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण एवं लाइसेंस व्यवस्था को अपेक्षाकृत सरल बनाया गया। शोध में पूंजी निवेश के विभिन्न स्वरूपों सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, घरेलू पूंजी निर्माण तथा विदेशी निवेश का आर्थिक विकास के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में यह देखा गया है कि पूंजी निवेश में वृद्धि केवल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसके माध्यम से आधुनिक तकनीक का हस्तांतरण, औद्योगिक विविधीकरण, परिवहन एवं संचार सुविधाओं का विस्तार, वित्तीय संस्थाओं का विकास तथा बाजार की कार्यक्षमता में सुधार भी संभव होता है। नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा दिया। इसके फलस्वरूप सेवा क्षेत्र, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर विकसित हुए। साथ ही, विदेशी पूंजी के आगमन ने पूंजी संसाधनों की उपलब्धता के साथ–साथ प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कौशल और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को भी प्रभावित किया। इस प्रकार शोध का एक प्रमुख पक्ष यह निर्धारित करना है कि नई आर्थिक नीति के माध्यम से पूंजी निवेश में हुए विस्तार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक परिवर्तन प्रक्रिया को किस सीमा तक प्रभावित किया और आर्थिक विकास को अधिक गतिशील बनाने में उसकी वास्तविक भूमिका क्या रही।

शोध के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि नई आर्थिक नीति ने भारत में पूंजी निवेश के वातावरण को व्यापक रूप से परिवर्तित किया और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निजी एवं विदेशी निवेश के विस्तार ने उत्पादन, तकनीकी आधुनिकीकरण, उद्यमिता तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया, जबकि आधारभूत संरचना में निवेश ने आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए आवश्यक भौतिक आधार को मजबूत करने में सहायता प्रदान की। इसके साथ ही, पूंजी निवेश के प्रभावों का मूल्यांकन करते समय केवल सकल घरेलू उत्पाद अथवा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि को पर्याप्त संकेतक नहीं माना जा सकता, क्योंकि आर्थिक विकास की वास्तविक सफलता रोजगार सृजन, आय–वितरण, गरीबी में कमी, क्षेत्रीय संतुलन तथा सामाजिक अवसरों के विस्तार से भी निर्धारित होती है। अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि नई आर्थिक नीति से प्राप्त लाभ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और सामाजिक वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच सके। कृषि क्षेत्र, लघु एवं कुटीर उद्योग, असंगठित क्षेत्र तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को पूंजी एवं तकनीकी संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ परिस्थितियों में पूंजी–प्रधान विकास ने रोजगार की अपेक्षाकृत सीमित वृद्धि तथा क्षेत्रीय असमानताओं जैसी चुनौतियों को भी जन्म दिया। इसलिए शोध का निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि नई आर्थिक नीति को केवल अधिक पूंजी आकर्षित करने की नीति के रूप में न देखकर उसे समावेशी, रोजगारपरक और संतुलित आर्थिक विकास के व्यापक उद्देश्य से जोड़ना आवश्यक है। सार्वजनिक और निजी निवेश के बीच प्रभावी समन्वय, घरेलू बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विस्तार, लघु एवं मध्यम उद्यमों को वित्तीय सुविधा तथा सामाजिक क्षेत्रों में पर्याप्त सार्वजनिक व्यय के माध्यम से पूंजी निवेश के लाभों को व्यापक बनाया जा सकता है। अतः समग्र रूप से नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश की संभावनाओं को उल्लेखनीय रूप से विस्तारित किया है, किंतु भविष्य की आर्थिक नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेश की मात्रा के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता, उत्पादकता, सामाजिक उपयोगिता और उसके लाभों के न्यायपूर्ण वितरण को कितनी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाता है।

शोध कुंजी पूंजी निवेश, आर्थिक विकास, नई आर्थिक नीति, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, घरेलू निवेश, सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, पूंजी निर्माण, औद्योगिक विकास, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, तकनीकी विकास, आधारभूत संरचना, उत्पादकता, वित्तीय विकास, औद्योगिकीकरण, क्षेत्रीय विकास, समावेशी विकास, आय–वितरण, आर्थिक असमानता, विदेशी पूंजी, निवेश नीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार, प्रतिस्पर्धा, उद्यमिता विकास।

शोध की प्रस्तावना

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में पूंजी निवेश को किसी भी राष्ट्र की उत्पादन क्षमता, रोजगार सृजन, तकनीकी उन्नति तथा आधारभूत संरचना के विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध पूंजी का प्रभाव केवल उद्योगों की स्थापना अथवा उत्पादन में वृद्धि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कृषि, उद्योग, सेवा, परिवहन, संचार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वित्तीय क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के विकास को भी प्रभावित करता है। पर्याप्त पूंजी निवेश के अभाव में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग संभव नहीं हो पाता और आर्थिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी रहती है। विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया का महत्व अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वहां उत्पादन के आधुनिक साधनों, तकनीकी उपकरणों, आधारभूत सुविधाओं तथा उद्यमशील गतिविधियों के विस्तार के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश में आर्थिक विकास के साथ–साथ जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताओं, रोजगार की मांग, क्षेत्रीय असमानताओं और सामाजिक कल्याण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पूंजी निवेश की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पूंजी निवेश के माध्यम से नई उत्पादन इकाइयों की स्थापना, पुरानी इकाइयों का आधुनिकीकरण, तकनीकी दक्षता में वृद्धि तथा उत्पादकता के विस्तार को गति मिलती है। इसके अतिरिक्त निवेश से बाजार में मांग का विस्तार, आय के नए स्रोतों का निर्माण और आर्थिक गतिविधियों में गतिशीलता उत्पन्न होती है। इस दृष्टि से पूंजी निवेश को आर्थिक विकास का साधन ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम भी माना जा सकता है।

भारत की आर्थिक विकास यात्रा में पूंजी निवेश की भूमिका को समझने के लिए नई आर्थिक नीति का अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1991 में गंभीर आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के बीच भारत ने आर्थिक सुधारों की ऐसी प्रक्रिया आरंभ की, जिसने अर्थव्यवस्था के नियामक, औद्योगिक और निवेश संबंधी ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित इस नीति का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों पर अनावश्यक नियंत्रण को कम करना, निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना, विदेशी पूंजी को आकर्षित करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से अधिक प्रभावी रूप से जोड़ना था। नई आर्थिक नीति के पश्चात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी पूंजी निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हुआ। इससे दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, ऊर्जा तथा आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए अवसर विकसित हुए। पूंजी निवेश में वृद्धि ने उत्पादन क्षमता और तकनीकी आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित किया, किंतु इसके साथ रोजगार, आय–वितरण, क्षेत्रीय असमानता, कृषि क्षेत्र की स्थिति तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों से संबंधित चुनौतियां भी सामने आईं। इसलिए नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन केवल आर्थिक वृद्धि की दर या निवेश की मात्रा के आधार पर करना पर्याप्त नहीं हैय इसके सामाजिक, क्षेत्रीय और रोजगारपरक प्रभावों का अध्ययन भी आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन में आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की प्रकृति एवं आवश्यकता, नई आर्थिक नीति के प्रमुख प्रावधानों, निवेश के विभिन्न स्रोतों तथा आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव का विश्लेषण किया जाएगा। साथ ही यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाएगा कि नई आर्थिक नीति ने पूंजी निवेश को किस सीमा तक प्रोत्साहित किया और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगार तथा समावेशी विकास को कितना लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार अध्ययन का व्यापक उद्देश्य पूंजी निवेश और नई आर्थिक नीति के पारस्परिक संबंध को समझते हुए भारतीय आर्थिक विकास की उपलब्धियों तथा सीमाओं का संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करना है।

शोध के सोपान

विषय का चयन एवं समस्या का निर्धारण : इस शोध का प्रथम सोपान आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की भूमिका तथा नई आर्थिक नीति के प्रभावों को अध्ययन की केंद्रीय समस्या के रूप में निर्धारित करना है। इस चरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि पूंजी निवेश आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार, तकनीकी

उन्नति और आधारभूत संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा वर्ष 1991 के पश्चात लागू नई आर्थिक नीति ने निवेश के वातावरण में क्या परिवर्तन किए।

अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण : इस चरण में शोध के प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। इनमें पूंजी निवेश की अवधारणा एवं स्वरूप का अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी निवेश की भूमिका का विश्लेषण, नई आर्थिक नीति के प्रमुख प्रावधानों का मूल्यांकन तथा निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास पर पड़े प्रभावों का अध्ययन प्रमुख हैं।

संबंधित साहित्य का अध्ययन : इस सोपान में पूंजी निवेश, आर्थिक विकास, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण तथा नई आर्थिक नीति से संबंधित पुस्तकों, शोध–प्रबंधों, शोध–पत्रों, सरकारी रिपोर्टों एवं अन्य प्रामाणिक स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। पूर्ववर्ती अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर शोध की सैद्धान्तिक एवं वैचारिक पृष्ठभूमि निर्मित की जाती है।

शोध सामग्री एवं आंकड़ों का संकलन :इस चरण में अध्ययन के लिए आवश्यक प्राथमिक एवं द्वितीयक सामग्री का संकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, सकल पूंजी निर्माण, सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य संबंधित आर्थिक संकेतकों से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है।

आंकड़ों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण : संकलित आंकड़ों को विषय एवं आवश्यकता के अनुसार वर्गीकृत करके उनका तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। नई आर्थिक नीति से पूर्व तथा उसके पश्चात पूंजी निवेश की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हुए आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास, रोजगार तथा क्षेत्रीय विकास पर उसके प्रभावों को समझने का प्रयास किया जाता है।

नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन :इस सोपान में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से पूंजी निवेश में हुए परिवर्तनों का मूल्यांकन किया जाता है। विदेशी निवेश के विस्तार, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, तकनीकी हस्तांतरण, प्रतिस्पर्धा तथा औद्योगिक विकास के साथ–साथ क्षेत्रीय असमानता, रोजगार संबंधी चुनौतियों और सामाजिक प्रभावों को भी अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है।

निष्कर्षों का निर्धारण :विश्लेषण से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि पूंजी निवेश ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में किस प्रकार योगदान दिया तथा नई आर्थिक नीति अपने निवेश संबंधी उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त करने में सफल रही। उपलब्ध निष्कर्षों को तार्किक एवं वस्तुनिष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सुझाव एवं उपसंहार :अंतिम सोपान में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर पूंजी निवेश को अधिक प्रभावी, रोजगारपरक, क्षेत्रीय रूप से संतुलित तथा समावेशी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके साथ ही नई आर्थिक नीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों का समग्र मूल्यांकन करते हुए अध्ययन का उपसंहार प्रस्तुत किया जाता है।

शोध का महत्व

आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग पर्याप्त पूंजी के बिना संभव नहीं होता। पूंजी निवेश के माध्यम से उत्पादन के साधनों का विस्तार, नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, मौजूदा उद्योगों का आधुनिकीकरण तथा तकनीकी दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। इससे उत्पादन क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय आय के विस्तार को आधार प्राप्त होता है। भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी निवेश का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहां आर्थिक विकास के साथ–साथ रोजगार, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असमानता और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार जैसी समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। निवेश के माध्यम से सड़क, रेल, बिजली, सिंचाई, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा सकता है, जो दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक आधार निर्मित करती हैं। इस प्रकार पूंजी निवेश केवल उत्पादन एवं आय में वृद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक क्षमता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण साधन भी है।

नई आर्थिक नीति के संदर्भ में पूंजी निवेश के महत्व का अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वर्ष 1991 के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी नीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन हुए। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया तथा विदेशी पूंजी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में

प्रतिस्पर्धा, तकनीकी हस्तांतरण, आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों और वैश्विक बाजारों से जुड़ाव को प्रोत्साहन मिला। नई आर्थिक नीति के प्रभावों का अध्ययन यह समझने में सहायता करता है कि पूंजी निवेश ने औद्योगिक विकास, सेवा क्षेत्र के विस्तार, रोजगार सृजन, तकनीकी आधुनिकीकरण तथा आर्थिक वृद्धि को किस सीमा तक प्रभावित किया। साथ ही, इसका महत्व इसलिए भी है कि निवेश से प्राप्त लाभों का वितरण सभी क्षेत्रों और वर्गों में समान नहीं रहा है। कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योग, असंगठित क्षेत्र तथा पिछड़े क्षेत्रों के संदर्भ में निवेश की उपलब्धता और उसके प्रभावों का स्वतंत्र मूल्यांकन आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्ययन नई आर्थिक नीति की सफलता को केवल निवेश की मात्रा अथवा आर्थिक वृद्धि की दर से नहीं, बल्कि निवेश की गुणवत्ता, उत्पादकता, रोजगारपरकता, क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास के आधार पर समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

इस अध्ययन का शैक्षणिक महत्व भी पर्याप्त है, क्योंकि इसके माध्यम से पूंजी निवेश और आर्थिक विकास के पारस्परिक संबंध को सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से समझने का अवसर प्राप्त होता है। नई आर्थिक नीति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन का विश्लेषण नीति–निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, शोधार्थियों तथा आर्थिक संस्थाओं के लिए उपयोगी आधार प्रदान कर सकता है। अध्ययन से यह समझने में सहायता मिलती है कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित किया जा सकता है तथा विदेशी पूंजी का उपयोग राष्ट्रीय विकास के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप किस प्रकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी निवेश को रोजगार सृजन, क्षेत्रीय विकास और सामाजिक कल्याण से जोड़ना आर्थिक नीति की दीर्घकालीन सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए इस शोध का महत्व केवल नई आर्थिक नीति के मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ऐसी निवेश नीतियों के निर्माण की दिशा में भी उपयोगी आधार प्रस्तुत करता है, जिनका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ रोजगार, उत्पादकता, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी विकास सुनिश्चित करना हो।

शोध के उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की अवधारणा, स्वरूप एवं महत्व का अध्ययन करना।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में पूंजी निवेश की भूमिका का विश्लेषण करना।
- नई आर्थिक नीति के प्रमुख उद्देश्यों एवं प्रावधानों का अध्ययन करना।
- उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के पूंजी निवेश पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- नई आर्थिक नीति के पश्चात सार्वजनिक एवं निजी निवेश में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करना।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी पूंजी के भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान का विश्लेषण करना।
- पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना।
- पूंजी निवेश के माध्यम से रोजगार सृजन तथा उत्पादकता वृद्धि पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।
- नई आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप तकनीकी विकास एवं आधुनिकीकरण में पूंजी निवेश की भूमिका का अध्ययन करना।
- पूंजी निवेश के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना।

शोध का निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन "आर्थिक क्षेत्र में पूंजी निवेश की भूमिका : नई आर्थिक नीति का मूल्यांकन" के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पूंजी निवेश आर्थिक विकास की आधारभूत एवं गतिशील शक्ति है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता के विस्तार, औद्योगिक विकास, तकनीकी आधुनिकीकरण, आधारभूत संरचना के निर्माण तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए पर्याप्त एवं प्रभावी पूंजी निवेश आवश्यक होता है। भारत जैसे विकासशील देश में पूंजी की आवश्यकता केवल आर्थिक वृद्धि को गति देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के संतुलित विकास, क्षेत्रीय असमानताओं में कमी तथा सामाजिक–आर्थिक अवसरों के विस्तार से भी संबंधित है। अध्ययन से यह तथ्य सामने आता है कि वर्ष 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था की निवेश व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र की भूमिका में विस्तार हुआ तथा विदेशी निवेश के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल वातावरण विकसित हुआ। इससे पूंजी के नए स्रोत

उपलब्ध हुए, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अनेक क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक तथा प्रबंधन पद्धतियों का प्रवेश हुआ। विशेष रूप से उद्योग, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं तथा आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का विस्तार हुआ। इस प्रकार नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक खुला, प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था से संबद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नई आर्थिक नीति ने भारत में पूंजी निवेश के लिए व्यापक संभावनाएं विकसित कीं और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की। सार्वजनिक निवेश ने आधारभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास में आधार प्रदान किया, जबकि निजी तथा विदेशी निवेश ने उत्पादन, तकनीकी नवाचार, प्रतिस्पर्धा और उद्यमिता को गति दी। दोनों क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घकालीन विकास क्षमता को मजबूत कर सकता है। भविष्य की निवेश नीति में केवल अधिक पूंजी आकर्षित करने के स्थान पर उत्पादक, रोजगारपरक, क्षेत्रीय रूप से संतुलित तथा समावेशी निवेश को प्राथमिकता देना आवश्यक है। घरेलू बचत एवं पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करने, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पर्याप्त वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने, पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करने से पूंजी निवेश के लाभों को व्यापक बनाया जा सकता है। अतः नई आर्थिक नीति को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी चरण माना जा सकता है, किंतु उसकी दीर्घकालीन सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार, सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय संतुलन और समान अवसरों को भी विकास नीति का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अग्रवाल, ए. एन., 2010, भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन।
- आहूजा, एच. एल., 2019, भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, एस. चंद एंड कंपनी।
- भल्ला, जी. एस., 2008, भारतीय अर्थव्यवस्था : उदारीकरण और सुधार, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स।
- दत्त, रुद्र एवं सुंदरम, के. पी. एम., 2018, भारतीय अर्थव्यवस्था, नई दिल्ली, एस. चंद एंड कंपनी।
- धर, पी. के., 2000, भारतीय अर्थव्यवस्था : आर्थिक सुधार और विकास, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।
- जिंगन, एम. एल., 2012, मौद्रिक अर्थशास्त्र, दिल्ली, वृंदा पब्लिकेशन्स।
- कबरा, के. एन., 2005, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस।
- मिश्रा, एस. के. एवं पुरी, वी. के., 2020, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुंबई, हिमालय पब्लिशिंग हाउस।
- पाण्डेय, राधेश्याम, 2015, भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास, जयपुर, साहित्य भवन।
- रंगराजन, सी., 2004, भारतीय अर्थव्यवस्था : समकालीन मुद्दे, नई दिल्ली, अकादमिक फाउंडेशन।
- उर्स, एच. आर., 2011, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण, नई दिल्ली, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स।
- वर्मा, एम. एल., 2014, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएँ और संभावनाएँ, जयपुर, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।